Expenditure incurred by BICL on Litigations

604. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1771 given in the Rajya Sabha on 9th March, 1992 and state :

(a) whether all the bills of lawyers engaged in Allahabad and Kanpur for the litigations initiated after June, 1991 or for contesting thereof have not been included to determine the actual cost on the litigations during the period.

(b) whether the concerned lawyers have not been asked by the British India Corporation Limited to submit their complete bills before giving out the facts of the case;

(c) whether the Secretary of the Company is also rendering consultancy services both within the company as well as to outsiders and has been equally charging cost and expenses thereof from the various associate or subsidiary companies of BICL; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) The bills received from the lawyers paid upto Feb., 92 were included in the expenditure incurred on litigation.

(b) The British India Corporation Ltd. has not given any direction/instructions to lawyers about billing.

(c) and (d) The Company Secretary is not rendering any consultancy services to any outsider. He is, however, advising the Subsidiary Associate Companies on the legal matters free of charge except Cawnpore Sugar Works Ltd. and Champaran Sugar Co. Ltd. for which, in accordance with the decision taken by the then Management Committees of the said Sugar Companies on 6-7-1990, he is being paid remuneration of Rs. 750 per month with effect from 1-4-1990 for rendering legal advice in the normal circumstances and when any time-consuming legal work is involved an amount of Rs. 500 per month depending on the extra quantum of work is also sanctioned.

वस्त्रों के निर्यात कोटे में वृद्धि करने के लिये भारत और अमरीका के बीच हुई बातचीत

605. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आशिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वस्त्रों के निर्यात संबंधी कोटे में वृद्धि करने के लिये भारत और अमरीका के बीच वाशिंगटन में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये सरकार द्वारा, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ताओं के अनुसरण में वर्ष 1992 के लिये अमरीकी बाजार में वस्त्र एवं क्लादिंग के निर्यात के लिये प्रवेश स्तरों के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ। इसके अनुसार कुछ निश्चित उत्पादों के कोटों में वृद्धि दी गई है। कुछ उत्पादों के बारे में अतिरिक्त लोचशीलताएं उपलब्ध होंगी जिससे निर्यात अवसरों में वृद्धि होगी। यह अपेक्षा की जाती है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप वर्ष 1992 के दौरान अमरीकी बाजार में निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

देश में कपास के भंडार की स्थिति

606. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री रणजीत सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1992 को "द इकोनोमिक्स टाइम्स" में "काटन प्रोडक्शन इम्प्रूव्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;